788.

एसोसिएटेड बैंकिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

बनाम

आयकर आयुक्त, बॉम्बे-1

निर्णय की तिथि: 22 अक्टूबर 1964

(के सुब्बा राव, जेसी शाह, एसएम सीकरी न्यायाधीश गण)

आयकर अधिनियम (1922 का 11), एस-एस 10 (1) और 10 (2) (xi) और (xv) खराब ऋणों का दायरा&यदि दावे की अनुमति देने से पहले बट्टे खाते मे डाल दिया जाना चाहिए&बैंक अधिकारी द्वारा गबन&यदि व्यापार हानि&घटना का समय।

निर्धारिती परिसमापन में एक बैंक था। आधिकारिक परिसमापक निर्धारण वर्ष 1948&49 के लिए एक रिर्टन भरा और कटौती के रूप में दावा कियाः-

(1) धारा 10 (2) (xi) भारतीय आय-कर अधिनियम 1992 बैंक के तहत ऋण जो अपरिवर्तनीय हो गए थे और (ii) धारा 10 (2) (xv) के तहत इसके एक अधिकारी द्वारा गवन की गई कुछ राशि और बैंक के पास थी अपने घटकों को भुगतान करना था। आयकर अधिकारियों और अपीलीय न्यायाधिकरण ने खराब ऋणों के भत्तें के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि खराब ऋणों को बैंक के खाते में बट्टे खातें में नहीं लिखा

गया था। उन्होंने गबन की गई राशि के भत्ते के दावे को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे राषि बैंक के व्यवसाय से संबंधित नहीं थी और किसी भी स्थिति में खाते के वर्ष में पता नहीं चलने पर उस वर्ष में नहीं हुआ था। जब मामलों को उच्च न्यायालय को भेजा गया तो न्यायालय ने न्याधिकरण से एक रिपोर्ट मॉगी जिसक बारे में

(i) क्या कोई ऋण वास्तव में अपरिवर्तनीय हो गया था और

(ii) वह वर्ष जिसमें गबन के परिणामस्वरूप बैंक को नुकसान हुआ था। न्यायाधिकरण ने बताया कि कुल ऋण रूपये 15,00,000 कम से कम खाते के वर्ष में अपरिवर्तनीय हो गया था और बैंक के अधिकारी द्वारा की गई चूक का पता परिसमापक को खाते के वर्ष की समाप्ति के बाद ही चला था। रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के खिलाफ निर्णय देते हुए कहा कि और (i) खराब ऋण अतिरिक्त कटौती नहीं थी क्योंकि उन्हें कभी माफ नहीं किया गया था और (ii) खाते के वर्ष के अंत में चूक के कारण बैंक को नुकसान हुआ था। निर्धारिती ने उच्चतम न्यायालय में अपील की।

निर्णितः

(i) बैंक रूपये का दावा करने का हकदार था। रूपये 15,00,000 खाते के वर्ष में खराब ऋण के रूप में (802 एफ&जी)

धारा 10 (2) (xi) में यह नहीं कहा गया हैं कि आयकर अधिकारी खराब या संदिग्ध ऋण की अनुमति तब तक नहीं दे सकता जब तक कि इसे लेखा पुस्तकों में बट्टे खाते में नहीं लिखा जाता हैं।

केवल यह कहता हैं कि वह वास्तव में बट्टे खाते में डाली गई राशि से अधिक किसी भी राशि को अपरिवर्तनीय नहीं होने देगा। यदि ऋण की राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए एक प्रविष्टि की अनुपस्थिति के लिए एक उचित स्पष्टीकरण है, तो इस तरह की अनुपस्थिति अपने आप में अधिकारी को अस्वीकार करने का आधार नहीं है, जो ऋणों की राशि का अनुमान लगाने के लिए अधिकार क्षेत्र हैं जो अपरिवर्तनीय हो गए है और उन्हें लाभ की गणना में उचित कटौती के रूप में अनुमति देते हैं। अधिकारी की शक्ति केवल एक निर्देश में सीमित हैं अर्थात् जब निर्धारिती ने अपने लेखा पुस्तकों में एक प्रविष्टि या प्रविष्टियां पोस्ट की है, तो अपरिवर्तनीय के रूप में अनुमानित राशि निर्धारिती द्वारा वास्तव में लिखी गई राशि से अधिक नहीं हैं।

इसका मतलब यह नहीं हैं कि एक निर्धारिती जो एक प्रविष्टि पोस्ट नहीं करने का विकल्प चुनता है वह उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं जिसने वास्तव में प्रविष्टियां पोस्ट की है क्योंकि वह हमेशा आयकर अधिकारी के इस निष्कर्ष पर पहुंचने का जोखित उठाता हैं कि उसे एक

प्रविष्टि पोस्ट करने के लिए नहीं चुना था, इस निष्कर्ष के अनुरूप हैं कि उसके कारण ऋण का कोई भी हिस्सा अपरिवर्तनीय नहीं हो गया हैं।

(794 ई&एफः 796 डी&एफः 797 जी&एच 798 बी&सी)

बेग डनलप एंड कपंनी लिमिटेड बनाम अतिरिक्त लाभ कर आयुक्त, पश्चिम बंगाल। (1954) 25 आई-टी-आर- 276, स्वीकृत।

789. एसोसिएटेड बैकिंग कॉरपोरेशन बनाम सी.आई.टी (शाह जे.)

(ii) अधिकारी द्वारा गबन की गई राशि बैंक व्यावसायिक हानि या कटौती के रूप में दावा करने का हकदार नहीं था। (802 G)

बैंक के अधिकारी अवमूल्यन के परिणामस्वरूप बैंक को नुकसान हुआ था। लेकिन धन की निकासी और दुरूपयोग का ज्ञान परिसमापक को लेखांकन वर्ष के बाद ही हुआ और इसलिए धारा 10 (2) (xv) के तहत राशि अनुमेय कटौती नहीं होगी। हालांकि गबन 1946 में हुआ था, लेकिन वे तब परिमापक को ज्ञात होने के पश्चात् एक व्यापारिक हानि के परिणामस्वरूप नहीं माना जा सकता था। किसी भी बैंक को गबन होते ही व्यापारिक हानि नहीं होती, भले ही बैंक को इसकी जानकारी हो या नहीं । जब तक राशि की वसूली की उचित संभावना है, व्यावसायिक दृष्टि से व्यापारिक हानि का परिणाम नहीं माना जाएगा। [800 D; 801 G-H]

एम-पी-वेंकटचलपति लायर बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास (1951), 20 एल. टी. आर 363 अनुमोदित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 956/1963.

बंबई उच्च न्यायालय के अपील संख्या 72/1957 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.04.1960 से उत्पन्न।

ए- वी-विष्वनाथ शास्त्री, जे-बी-दादाचंजी, ओ-सी- माथुर और अपीलार्थी की ओर से रविंदर नारायण।

सी-के-डाफ्टरी, महान्यायवादी, के-एन- राजागोपाला शास्त्री, वास्ते अपीलार्थी आर-एच-ढेबर और आर-एन-सचथे।

द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

शाह, जे.:

एम.सी.जवेरी को एसोसिएटेड बैंकिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सचिव नियुक्त किया गया था, और 14 अगस्त,1943 को पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत उन्हें व्यवसाय की देखरेख, प्रबंधन और संचालन, ऐसी दर या ब्याज की दरें जो वह किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के साथ या उसके बिना उचित समझे, उधार देने और उधार दिए गए या अग्रिम किए गए किसी भी पैसे और उस पर सभी और उस पर सभी ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अच्छा निर्वहन प्राप्त करना और उधार लेना और बैंक की संपत्ति पर ऐसी शर्तों पर जो वह बैंक के लाभ के लिए उचित समझे। 5 मार्च, 1945 को जवेरी को बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया। 21 अप्रैल, 1947 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश से बैंक को अनिवार्य रूप से बंद करने का

आदेश दिया गया था और बैंक के व्यवसाय को समाप्त करने के लिए एक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया था। 23 अगस्त, 1949 को परिसमापक ने आकलन वर्ष 1948-49 के लिए एक रिटर्न प्रस्तुत किया, जिसमें 30 जून, 1947 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए मूल्यांकन वर्ष 1948-49 के लिए एक विवरणी प्रस्तुत की जिसमें 9,71,664 रुपये के व्यापार नुकसान की गणना की गई, लाभ और हानि खाते में सकल लाभ के मुकाबले 12,00,000 रुपये से अधिक की राशि ऋण के रूप में डेबिट की गई, जो वसूली योग्य नहीं थी।

790. [1965]1 एस-सी-आर

26 फरवरी, 1953 को परिसमापक ने आयकर अधिकारी को सूचित किया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि सचिव द्वारा गबन की गई राशि सहित बैंक का खराब ऋण 48,50,952 रुपये है।

यह आम आधार है कि राशि की पुस्तकों को समायोजित करने और वसूली योग्य राशियों को बट्टे खाते में डालने वाली प्रविष्टियों को उनके रिटर्न दाखिल करने से पहले या यहां तक कि कार्यवाही ट्रिब्यूनल तक पहुंचने से पहले भी बही-खातों में पोस्ट नहीं किया गया था। विभागीय प्राधिकारियों और अधिकरण ने इस आधार पर खराब ऋणों के भत्ते के दावे को खारिज कर दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) (xi) के अनुसार बैंक के बही-खातों में खराब ऋणों को बट्टे खाते में नहीं डाला

गया था। सचिव द्वारा गबन के कारण होने वाली हानि के रूप में 10,15,000 रुपये और 98892 रुपये के भत्ते के दावे को विभागीय अधिकारियों द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि गबन बैंक के व्यवसाय से संबंधित नहीं था और इसे व्यवसाय के दौरान बैंक को हुए नुकसान के रूप में नहीं माना जा सकता था। और किसी भी घटना में खाते के वर्ष में नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उस वर्ष में इसका पता नहीं लगाया गया था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने दो कारणों में से दूसरे के लिए विभागीय अधिकारियों से सहमत था। ।

ट्रिब्यूनल ने अधिनियम की धारा 66 (1) के तहत दो प्रश्नों का उल्लेख किया, जिन्हें बाद में उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया था:

(1) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर करदाता 38,35,654 रुपये या उससे कम राशि के खराब ऋण का दावा करने का हकदार है?

(2) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर करदाता 10,15,000 रुपये और 98892 रुपये की दो रकम की हानि का आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के तहत कटौती के रूप में दावा करने का हकदार है?

उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के साथ सहमति व्यक्त की कि खराब ऋणों के भत्ते के लिए दावा धारा 10 (2) (xi) के तहत कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ऋण को बैंक के बही-खातों में बट्टे खाते में नहीं डाला गया था। लेकिन परिसमापक के वकील के अनुरोध पर उन्होंने ट्रिब्यूनल को इस सवाल पर एक पूरक विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा कि क्या ऋण वास्तव में खाते के वर्ष के दौरान अप्राप्य हो गए थे, और क्या वे बैंक के व्यवसाय के दौरान उत्पन्न ऋण थे। उच्च न्यायालय की राय थी कि मामले के बयान में निर्धारित तथ्य उन्हें दूसरे प्रश्न पर उत्तर दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

791. एसोसिएटेड बैकिंग कॉरपोरेशन बनाम सी.आई.टी (शाह जे.)

दूसरा प्रश्न, ट्रिब्यूनल से सचिव को सौंपी गई शक्तियों के बारे में एक पूरक विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा, और सचिव द्वारा गबन के परिणामस्वरूप बैंक को किस वर्ष नुकसान हुआ। ट्रिब्यूनल ने बताया कि "कम से कम 15,00,000 रुपये" तक के ऋण खाते के वर्ष में वसूली योग्य नहीं थे, और सचिव ने लेखा पुस्तकों में काल्पनिक प्रविष्टियों को पोस्ट करने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी (जिसकी एक प्रति रिपोर्ट में संलग्न की गई थी) के तहत सौंपी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया था। लेकिन रूपये 18,00,000 और रूपये 98892 का सचिव द्वारा गबन परिसमापक को 30 जून, 1947 को समाप्त होने वाले खाते के वर्ष के बाद ही ज्ञात हुई।

मामले की आगे की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने कहा कि वे पिछली सुनवाई में दर्ज किए गए इस निष्कर्ष से बंधे थे कि खराब ऋण स्वीकार्य कटौती नहीं थे क्योंकि ऋण कभी भी बैंक के बही-खातों में बट्टे खाते में नहीं डाले गए थे, और यह कि जब किसी सेवक या निर्धारिती के एजेंट द्वारा गबन या विमुद्रीकरण से होने वाली हानि होती है, तो प्रत्येक के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। मामला, और उस संबंध में कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के विचार में 10,15,000 रुपये का नुकसान तब नहीं हुआ जब बैंक के बही-खातों में सचिव के कहने पर फर्जी प्रविष्टियां पोस्ट की गई थीं, बल्कि बहुत बाद में हुई । रुपये 98,892 की वस्तु भी इसी कारण से खाते के वर्ष में व्यापार हानि के रूप में स्वीकार्य नहीं थी। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के साथ, इस अपील को बैंक के परिसमापक द्वारा प्राथमिकता दी जाती है।

इस बात पर विचार करते हुए कि क्या बही-खातों में बट्टे खाते को बट्टे खाते में डालना खराब ऋणों के लिए भत्ते की स्वीकार्यता की एक शर्त है, सबसे पहले एस 10 (2) (xi) की शर्तों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। खंड में प्रावधान है:

(2) ऐसे लाभ या लाभ की गणना निम्नलिखित भत्ते देने के बाद की जाएगी, अर्थात्: –

(xi) जब करदाता के व्यवसाय, व्यवसाय या व्यवसाय के किसी भाग के संबंध में खाते नकद आधार पर नहीं रखे जाते हैं, तो उसके व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के उस भाग के संबंध में निर्धारिती को देय और संदिग्ध ऋणों के संबंध में ऐसी राशि, और बैंकिंग या साहूकारी व्यवसाय करने वाले करदाता के मामले में, ऐसे व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए गए ऋणों के संबंध में आयकर अधिकारी के रूप में की गई ऐसी राशि अप्राप्य होने का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उस राशि से अधिक नहीं जो वास्तव में निर्धारिती के बही-खातों में अप्राप्य के रूप में बट्टे खाते में डाला गया है:

792 [1965]1 एस-सी-आर

परंतुक

निर्धारिती एक बैंकिंग कंपनी है; इसने अपने कारोबार के सामान्य क्रम में ऋण प्रदान किए हैं और न्यायाधिकरण के निष्कर्षों पर, 15,00,000 रुपये के मूल्य के ऋणों को खाते के वर्ष में अप्राप्य होने का अनुमान है। क्या इस राशि को कर योग्य आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती है, जब इसे खाते की पुस्तकों में अप्राप्य के रूप में बट्टे खाते में नहीं लिखा गया है?

यह करदाता का काम है कि वह उन ऋणों के संबंध में भत्ते का दावा करे जो उसकी वापसी में या रिटर्न के साथ दिए गए विवरण में वसूली

योग्य नहीं हैं। अपने पूरक बयान में, परिसमापक ने दावा किया कि 48,50,952 रुपये की राशि को खाते के वर्ष में खराब ऋण के रूप में माना जाना चाहिए। वहां यह स्पष्ट था कि परिसमापक द्वारा उन राशियों को खराब ऋण के रूप में मानने का दावा किया गया था जिन्हें खाते के वर्ष में वसूली योग्य नहीं माना गया था। लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि यह खराब ऋणों के भत्ते की स्वीकार्यता की शर्त है कि एक प्रविष्टि या प्रविष्टियों को खातों की पुस्तकों में पोस्ट किया जाना चाहिए, जो ऋणों को अप्राप्य के रूप में लिखते हैं।

आयकर अधिकारी को अधिनियम के अनुसार उन ऋणों को अप्राप्य के रूप में अनुमान लगाने की शक्ति सौंपी गई है जिन्हें खराब या संदिग्ध के रूप में दावा किया जाता है, लेकिन यह शक्ति इस प्रतिबंध के अधीन है कि भत्ता वास्तव में बट्टे खाते में डाली गई राशि से अधिक नहीं होगा। यदि करदाता ने अपने बही-खातों में एक निश्चित राशि को वसूली योग्य राशि के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया है, तो आयकर अधिकारी, भले ही उसका अनुमान बट्टे खाते में डाली गई राशि से अधिक हो, वास्तव में बट्टे खाते में डाली गई राशि से अधिक राशि की अनुमति नहीं दे सकता है। क्या यह कहा जा सकता है कि जब करदाता ने खराब या संदिग्ध ऋण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी राशि को बट्टे खाते में डालने वाली प्रविष्टियों को बही-खातों में पोस्ट नहीं किया है, तो "खराब ऋण" शीर्षक के तहत अनुमेय कटौती की अनुमति देने के लिए आयकर अधिकारी की शक्ति

पर कोई प्रतिबंध नहीं है? इस प्रश्न पर उच्च न्यायालयों में विचारों का टकराव है। चागला सी.जे. ने अपील के तहत अपने फैसले में कहा कि यह विचार कि खाते की पुस्तिका में बट्टे खाते को बट्टे खाते में डालना एक खराब या संदिग्ध ऋण की स्वीकार्यता के लिए एक शर्त है, उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसे न्यायालयों ने धारा 10 (2) (xi) की व्याख्या करते समय कई वर्षों तक लगातार अपनाया था।

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा:

पीठ ने कहा, 'हमें ऐसे किसी भी मामले की जानकारी नहीं है जहां विभाग या करदाता ने कभी इस न्यायालय में यह दलील दी हो कि कोई करदाता फंसे कर्ज के रूप में एक निश्चित राशि का हकदार है और

793. एसोसिएटेड बैकिंग कॉरपोरेशन बनाम सी.आई.टी (शाह जे.)

वास्तव में यह राशि उसके बही-खातों में बट्टे खाते में नहीं डाली गई है। लेकिन स्थापित प्रथा के अलावा, इस न्यायालय के फैसले भी हैं जो धारा के उस दृष्टिकोण पर आगे बढ़े हैं।

बेग डनलप एंड कंपनी लिमिटेड बनाम कमिश्नर आयकर आयोग कलकत्ता उच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल (1954) 25 आईटीआर 276 पृष्ठ 284 पर (एआईआर 1954 कैल 600 पृष्ठ 603 पर) ने इसके विपरीत राय व्यक्त की है। चक्रवर्ती, सी.जे., न्यायालय का निर्णय देने वाले ने कहा कि धारा 10 (2) (xi) के अंतिम खंड द्वारा आयकर अधिकारी को ऐसी राशि की

अनुमति देने का विवेकाधिकार दिया जाता है जिसे वह स्वयं अधिकतम सीमा के रूप में वसूल करने योग्य होने का अनुमान लगा सकता है या बल्कि एक ही समय में एक सीमा निर्धारित की जाती है, जिससे अधिक या उससे अधिक वह नहीं जा सकता है। संघर्ष को हल करने के लिए खाते के वर्ष में किए गए व्यवसाय के लाभ या लाभ की गणना में खराब ऋणों के भत्ते से संबंधित प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक है।

आयकर अधिनियम, 1922 के तहत, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, धारा 10 की उपधारा (2) में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के लाभ या लाभ की गणना में खराब या संदिग्ध ऋणों के भत्ते के लिए कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन खराब या संदिग्ध ऋणों को एस 10 (1) के तहत आवश्यक व्यावसायिक कटौती के रूप में ठीक से अनुमति दी जा सकती है। कमिश्नर आयकर विभाग, सी. पी. और बरार बनाम वी. एस. एम. चिटनवीस 59 इंड ऐप 290: (एआईआर 1932 पीसी 178) में न्यायिक समिति ने कहा कि एक ऋण जो खाते के वर्ष के दौरान खराब ऋण बन गया है, उसे उचित रूप से नुकसान के रूप में माना जा सकता है और मुनाफे से काटा जा सकता है। न्यायिक समिति ने पृष्ठ संख्या 296 पर अवलोकन किया।

> "हालांकि अधिनियम कहीं भी किसी व्यवसाय के खराब ऋण की कटौती को अधिकृत नहीं करता है, इस तरह की कटौती

आवश्यक रूप से स्वीकार्य है। किसी व्यवसाय के संबंध में आयकर के लिए क्या शुल्क लगाया जाता है, एक वर्ष के लाभ और लाभ हैं; और एक वर्ष के लाभ और लाभ की मात्रा का आकलन करते समय आवश्यक रूप से किए गए सभी नुकसानों को लिया जाना चाहिए, अन्यथा आप वास्तविक लाभ और लाभ पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन नुकसान उस वर्ष में होने वाले नुकसान होना चाहिए। आप एक वर्ष के लाभ और लाभ का पता लगाते समय, उस हानि को नहीं घटा सकते हैं जो वास्तव में उस वर्ष के शुरू होने से पहले हुई थी। यदि आपने ऐसा किया, तो आप वर्ष के वास्तविक लाभ और लाभ पर नहीं पहुंचेंगे।"

* इस प्रकार यह इस प्रकार है कि एक ऋण, जो वास्तव में किसी विशेष वर्ष की शुरुआत से पहले एक खराब ऋण बन गया था, उस वर्ष के मुनाफे का पता लगाने में ठीक से कटौती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि नुकसान उस वर्ष में कायम नहीं था।

(1) (1954) 25 आई.टी.आर. 276, 284.

(2) (2) (1932) एल.आर. 59 आई. ए. 290.

794. [1965]1 एस-सी-आर

तथापि, न्यायिक समिति ने ऋणों को बट्टे खाते में डालने वाली प्रविष्टियों को भत्ते के दावे की स्वीकार्यता की शर्त के रूप में अप्राप्य नहीं माना। यह सच है कि लेखांकन की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली में, यह दावा कि ऋण निषिद्ध हो गया है, जहां खातों को लेखांकन की वाणिज्यिक विधि के अनुसार बनाए रखा जाता है, एक प्रविष्टि या प्रविष्टियां-यदि देनदार के खाते में किसी उपयुक्त स्थान या पुस्तकों में स्थानों पर नहीं हैं, तो यह दर्ज करते हुए पोस्ट किया जाएगा कि निर्धारिती के विचार में ऋण अप्राप्य हो गया था, और इस तरह की प्रविष्टि या प्रविष्टियों के बिना, सामान्य मामलों में, वर्ष का लाभ और हानि खाता बनाना मुश्किल होगा। लेकिन प्रविष्टियां प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण के संबंध में होनी चाहिए जिसे निर्धारिती द्वारा बुरा या संदिग्ध माना जाता है: बुरे या संदिग्ध के रूप में माने जाने वाले ऋणों से संबंधित एक समग्र प्रविष्टि पर्याप्त हो सकती है।

चिटनविस के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के बाद 59 इंड ऐप 290: (एआईआर-1932 पीसी 178) विधायिका ने भारतीय आयकर (1939 का संशोधन अधिनियम 7) की धारा 11 को उप-धारा में शामिल किया है। (2) एस 10, जो स्पष्ट रूप से लाभ और लाभ की गणना में भत्ते के रूप में खराब या संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता से संबंधित है। संशोधित अधिनियम द्वारा शासित मामलों में निस्संदेह भत्ते के रूप में खराब या संदिग्ध ऋणों की स्वीकार्यता के प्रश्न को क़ानून के स्पष्ट प्रावधान के प्रकाश में निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि वाणिज्यिक लेखा, या व्यावसायिक

आवश्यकता के सामान्य विचारों पर। विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को ध्यान में रखना उचित है; खंड यह नहीं कहता है कि आयकर अधिकारी खराब या संदिग्ध ऋण की अनुमति नहीं दे सकता है, जब तक कि इसे बही-खातों में बट्टे खाते में नहीं डाला जाता है; इसमें केवल यह कहा गया है कि आयकर अधिकारी वास्तव में बट्टे खाते में डाली गई राशि से अधिक की किसी भी राशि को अप्राप्य के रूप में अनुमति नहीं देगा। इसलिए, यह आयकर अधिकारी पर निर्भर करता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि खाते के वर्ष में कौन से ऋण खराब या संदिग्ध हो गए हैं। इसके लिए आयकर अधिकारी द्वारा जांच की आवश्यकता होगी कि क्या कोई ऋण जो खराब या संदिग्ध होने का दावा किया गया है, वह अप्राप्य हो गया है और कितनी राशि के लिए। यदि करदाता ने एक समग्र प्रविष्टि पोस्ट की है, तो दर्ज की गई राशि के मूल्य से अधिक ऋण को मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अप्राप्य के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि उसने व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में प्रविष्टियां पोस्ट की हैं, तो मूल्यांकन प्राधिकारी की शक्ति पर प्रतिबंध ऐसे प्रत्येक ऋण के संबंध में काम करना चाहिए। हालांकि यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्तिगत ऋण के संबंध में, बही-खातों में बट्टे खाते को बट्टे खाते में डालना मुनाफे की गणना में इसके भत्ते की शर्त नहीं है।

(1) (1932) एल.आर. 59 आई. ए. 290.

795. एसोसिएटेड बैकिंग कॉरपोरेशन बनाम सी.आई.टी (शाह जे.)

हमारा ध्यान ऐसे किसी निर्णय की ओर नहीं दिलाया गया है (अपील के तहत दिए गए निर्णय को छोड़कर) जिसमें यह व्यवस्था दी गई है कि आयकर अधिकारी की उन ऋणों की कटौती की अनुमति देने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब करदाता के बही-खातों में एक प्रविष्टि पोस्ट की गई हो कि एक निश्चित राशि वसूली योग्य नहीं हो गई है। चागला ने अपने फैसले के दौरान जिन दो मामलों का उल्लेख बॉम्बे हाईकोर्ट की एक स्थापित प्रथा के उदाहरण के रूप में किया है, वे इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं। कमिश्नर आयकर विभाग और अतिरिक्त लाभ कर, सेंट्रल बॉम्बे 24 आईटीआर 537: (एआईआर 1954 बीओएम 277) करदाता ने अपने लाभ और लाभ के आकलन के दौरान दावा किया था कि कुछ ऋण खाते के वर्ष में वसूली के लिए संदिग्ध हो गए थे। करदाता ने वास्तव में लाभ और हानि खाते में दो राशियों को डेबिट किया था और उन्हें सस्पेंस खाते में "संदिग्ध ऋण" शीर्षक के तहत जमा किया था। आयकर अधिकारियों ने कहा कि चूंकि करदाता के बही-खातों में देनदारों के व्यक्तिगत खातों में राशि जमा नहीं की गई थी, इसलिए ऋण को धारा द्वारा आवश्यक रूप से बट्टे खाते में नहीं डाला गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि कर्ज की राशि वास्तव में करदाता के बही-खातों में बट्टे खाते में डाल दी गई थी। अदालत ने उस मामले में कहा कि धारा 10 (2) (xi) ने यह मांग नहीं की कि खराब या संदिग्ध होने का दावा करने

वाले ऋणों को लिखने वाली व्यक्तिगत बही-खाता प्रविष्टियों को पोस्ट किया जाना चाहिए। उस मामले में न्यायालय को इस बात पर विचार करने के लिए नहीं बुलाया गया था कि क्या राशि को बट्टे खाते में डालने की प्रविष्टि के अभाव में आयकर अधिकारी को उस सीमा तक खराब या संदिग्ध ऋणों की अनुमति देने की अपनी शक्ति से वंचित किया गया है, जिसका अनुमान अधिकारी द्वारा लगाया गया है कि वह वसूली योग्य नहीं है। इस मामले में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि धारा 10 (2) (xi) के तहत एक भत्ते के रूप में खराब ऋण की स्वीकार्यता के लिए ऋण को बट्टे खाते में डालना एक पूर्ववर्ती शर्त है।

दूसरा मामला कर्मसे गोविंदजी बॉम्बे बनाम मुंबई का है। इनकम टैक्स विभाग, बॉम्बे सिटी (1957) 31 आईटीआर 953 (बॉम्बे) है। उस मामले में करदाता ने 1945 और 1946 में एक फिल्म निर्माता को कुछ ऋण की जमानत के बिना अग्रिम भुगतान किया था और नवंबर 1947 में ऋण को खराब ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया था। मामले में साक्ष्य के आधार पर आयकर अधिकारियों ने माना कि ऋण 1947 में अप्राप्य नहीं हो पाए थे, और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने धारा 66 (2) के तहत एक संदर्भ में कहा कि आयकर अधिकारियों का यह निष्कर्ष कि 1947 में ऋण खराब नहीं हुआ था, को सबूतों पर उचित नहीं माना जा सकता है। जाहिर है कि यह मामला सीधे तौर पर करदाता के बही-खातों

में रखे गए कर्ज को बट्टे खाते में डालने से संबंधित नहीं है, जो धारा 10 (2) (xi) के तहत भत्ते के लिए एक शर्त है।

796. [1965]1 एस-सी-आर

राजस्व के वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि खराब ऋण का भत्ता तब भी दिया जा सकता है जब आयकर अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान अप्राप्य राशि के रूप में राशि को बट्टे खाते में डालने वाली प्रविष्टि पोस्ट की गई हो। इसलिए विभाग का कहना है कि हालांकि खराब या संदिग्ध होने का दावा किए गए ऋण की राशि को बट्टे खाते में डालना भत्ते के लिए एक शर्त है, लेकिन रिटर्न जमा करने से पहले या आयकर अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कार्यवाही की सुनवाई समाप्त होने से पहले भी प्रविष्टि को पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। विधायिका ने ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया है कि किसी ऋण को बट्टे खाते में डालने वाली लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि को वसूल न किया जा सके, धारा 10(2)(xi) के तहत भत्ते के रूप में इसकी स्वीकार्यता की शर्त है और अधिनियम की योजना के आलोक में जांचे गए खंड में प्रयुक्त भाषा ऐसी व्याख्या के लिए बाध्य नहीं करती है। आयकर अधिकारी और इसलिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की शक्ति पर-निस्संदेह एक प्रतिबंध लगाया गया है। आयकर अधिकारी के लिए यह खुला नहीं है कि वह उस राशि से अधिक ऋणों को अप्राप्य के रूप में अनुमान लगाए जिसे करदाता अप्राप्य मानता

है। लेकिन अगर किसी पर्याप्त कारण से करदाता ने एक प्रविष्टि पोस्ट नहीं की है और वे उस चूक के लिए एक उचित स्पष्टीकरण है, किसी ऐसे ऋण की राशि को बट्टे खाते में डालने की प्रविष्टि का अभाव जो खराब या संदिग्ध हो गया है, जिसे प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही समाप्त होने से पहले किसी भी समय बही-खातों में उचित स्थान पर पोस्ट किया जा सकता है, अपने आप में आयकर अधिकारी के अधिकार क्षेत्र को ऋणों को वसूली योग्य के रूप में अनुमान लगाने से इनकार करने का आधार नहीं है। और इसे मुनाफे की गणना में उचित कटौती के रूप में अनुमति देना। पहली नजर में यह कुछ विरोधाभासी लग सकता है कि यदि करदाता ने वास्तव में अपनी बही-खातों में सामूहिक राशि के व्यक्तिगत ऋणों को वसूली योग्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया है, तो आयकर अधिकारी की शक्ति सीमित हो जाती है और वह जिस राशि को वसूली योग्य ऋण के रूप में अनुमति दे सकता है, वह वास्तव में बट्टे खाते में डाली गई राशि से अधिक नहीं हो सकती है; जहां बही-खातों में राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है, आयकर अधिकारी का अधिकार क्षेत्र बड़े पैमाने पर है और वह किसी भी राशि को अप्राप्य के रूप में अनुमति दे सकता है। लेकिन क़ानून के प्रावधानों को तकनीकी की संकीर्ण भावना में नहीं लिया जाना चाहिए। यह देखा जा सकता है कि खंड (xi) बुरे ऋणों का अनुमान लगाने की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है; यह खराब और संदिग्ध ऋणों के मद में भत्ता देने की शक्ति को सीमित करता है, जो

करदाता द्वारा अपने बही-खातों में वास्तव में बट्टे खाते में डाली गई राशि से अधिक राशि है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि यदि खराब ऋणों का आकलन करने के बाद, भत्ता देने की शक्ति के प्रयोग पर कोई स्पष्ट वैधानिक रोक नहीं है, तो शक्ति के प्रयोग पर रोक का कोई निहितार्थ विकसित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि ऐसा निहितार्थ अधिनियम की योजना पर न हो।

797. एसोसिएटेड बैकिंग कॉरपोरेशन बनाम सी.आई.टी (शाह जे.)

अधिनियम की योजना में हमें ऐसा कोई प्रतिबंध अनिवार्य रूप से नहीं मिलता है, क्योंकि सभी मामलों में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रविष्टि की अनुपस्थिति में, खराब ऋणों की राशि को बट्टे खाते में डालने का मतलब यह है कि खाते के वर्ष में कोई भी ऋण अप्राप्य नहीं हो जाता है।

हमारे विचार में चक्रवर्ती, सी. जे. सही थे जब उन्होंने बेग डनलप एंड कंपनी लिमिटेड के मामले (1954) 25 आईटीआर 276 में पृष्ठ 284 पर देखा: (एआईआर 1954 कैल 600 पृष्ठ 602 पर)

उन्होंने कहा, 'मैं यह कहने में पूरी तरह असमर्थ हूं कि आयकर कानून की धारा 10 (2) (11) के तहत अनिवार्य रूप से यह जरूरी है कि किसी भी राशि को किसी विशेष वर्ष में वसूली योग्य नहीं माना जा सके, ऐसी राशि या उससे अधिक राशि को वास्तव में करदाता के बही-खाते में

डाल दिया जाना चाहिए। यदि मैं इसकी शर्तों को याद करूं तो इस धारा की प्रासंगिक भाषा ऐसी है कि आयकर अधिकारी ऐसी राशि का अनुमान लगा सकता है जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है लेकिन यह वास्तव में बट्टे खाते में डाली गई राशि से अधिक नहीं है। मेरे विचार से इस भाषा का अर्थ यह है कि जहां आयकर अधिकारी को ऐसी राशि की अनुमति देने का विवेकाधिकार दिया गया है, जिसे वह स्वयं अप्राप्य मान सकता है, वहीं एक ही समय में अधिकतम सीमा या उससे अधिक की सीमा निर्धारित की गई है, जिससे अधिक या उससे अधिक वह नहीं जा सकता है। इस धारा की यह भी अपेक्षा प्रतीत नहीं होती है कि जिस ऋण को आयकर अधिकारी अप्राप्य मान सकता है, उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से इस धारा का मतलब यह है कि यदि करदाता ने वास्तव में किसी विशेष वर्ष में किसी ऋण को वसूली योग्य नहीं मानते हुए बट्टे खाते में डाल दिया है, तो आयकर अधिकारी को उस वर्ष के लिए खराब ऋण के संबंध में भत्ता देते समय, उस राशि से अधिक कुछ भी करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिसे करदाता ने खुद बट्टे खाते में डाला है।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक करदाता जो खराब या संदिग्ध ऋणों के बारे में खातों की पुस्तिका में प्रविष्टि पोस्ट नहीं करने का विकल्प चुनता है, वह खुद को उस करदाता की तुलना में बेहतर स्थिति में रखता है, जिसने वास्तव में अपने बही-खातों में अप्राप्य राशि के रूप में बकाया राशियों को पोस्ट किया है। उनके समक्ष रखी गई सामग्रियों के

संबंध में, आयकर अधिकारी के लिए यह निष्कर्ष निकालना हमेशा खुला रहता है कि यह तथ्य कि करदाता ने प्रविष्टि पोस्ट करने का विकल्प नहीं चुना है, इस परिस्थिति के अनुरूप है कि खाते के वर्ष में उसके बकाया ऋण का कोई भी हिस्सा खराब या संदिग्ध नहीं हो गया है और इसलिए वसूली योग्य नहीं है। और उस आधार पर उस दावे को अस्वीकार करना जो सुनवाई में किया जा सकता है कि कुछ या सभी ऋण खराब या संदिग्ध हो गए थे।

(1) (1954) 25 आई.टी.आर. 276,

798. [1965]1 एस-सी-आर

यहां तक कि जब बही-खातों में कोई प्रविष्टि पोस्ट नहीं की गई है, तो प्रश्न आयकर अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों का है ताकि लाभ और लाभ की गणना में कटौती की अनुमति दी जा सके। यदि आयकर अधिकारी कुछ ऋणों को वसूली योग्य नहीं मानता है, तो यह धारा 10 (2) (xi) के तहत मुनाफे की गणना में इसकी अनुमति देने की उसकी शक्ति के भीतर होगा। यह शक्ति केवल एक दिशा में सीमित है, अर्थात्, जहां करदाता ने खातों की पुस्तकों में एक प्रविष्टि या प्रविष्टियां पोस्ट की हैं, तो अप्राप्य के रूप में अनुमानित की जाने वाली राशि उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे वास्तव में निर्धारिती द्वारा वसूली योग्य के रूप में बट्टे खाते में डाला गया है।

1961 के आयकर अधिनियम 43 के तहत, धारा 36 (1) (vii) द्वारा किसी भी ऋण या उसके हिस्से की राशि, जो पिछले वर्ष में खराब ऋण बन गई है, को धारा 28 के तहत आय की गणना में अनुमति दी जानी है; लेकिन वह भत्ता उपधारा (2) के अधीन है, जिसमें जहां तक यह प्रावधान है कि

"बुरे ऋण या उसके एक भाग के लिए कोई कटौती करने में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे: –

"(i) ऐसी किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा ऋण या उसका हिस्सा न हो;

(ए) को उस पिछले वर्ष या पिछले वर्ष के निर्धारिती की आय की गणना करते समय ध्यान में रखा गया है या बैंकिंग या धन उधार के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उधार दिए गए धन का प्रतिनिधित्व करता है जो निर्धारिती द्वारा किया जाता है, और

(बी) को पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में अप्राप्य के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

(ii) X X X X

(iii) X X X X

(iv) X X X X"

यह स्पष्ट है कि सामग्री खंड को पूरी तरह से फिर से तैयार किया गया है और विधायिका ने अपना इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है।

दूसरे प्रश्न से निपटने में कुछ और तथ्य बताए जा सकते हैं। सचिव एम. सी. जवेरी को प्रबंधन की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थीं और बैंक के निदेशक लापरवाह बने हुए प्रतीत होते थे। सचिव ने बैंक की परिसंपत्तियों में से बड़ी राशि निकालने में मदद की। 1 नवंबर, 1946 को बैंक ने भोपाल सरकार के साथ भोपाल सरकार द्वारा जारी रुपये 2 करोड़ के ऋण के लिए एक अंडरराइटिंग समझौता किया।

799. एसोसिएटेड बैंकिंग कॉरपोरेशन बनाम सी.आई.टी (शाह जे.)

3 दिसंबर, 1946 को वी. आर. रानाडे एंड संस ने भोपाल सरकार के ऋण को खरीदने के लिए बैंक में आवेदन किया और बैंक को रुपये 15 लाख की पूरी राशि भेज दी। यह राशि पहले विविध जमा खाते में जमा की गई थी, लेकिन सचिव के कहने पर विविध जमा खाते में प्रविष्टि को उलट दिया गया और 15 लाख रुपये की राशि को छोटी राशि में विभाजित किया गया और अलग-अलग नामों से खाता पुस्तकों में जमा किया गया। वी. आर. रानाडे एंड संस ने ऋण प्रमाण पत्र की डिलीवरी के लिए दबाव डाला और सचिव ने उन्हें बैंक ऑफ भोपाल लिमिटेड से प्राप्त रुपये 15 लाख के प्रमाण पत्र के लिए एक जाली आवंटन पत्र दिया। बैंक को बंद करने का आदेश दिए जाने के बाद, वी. आर. रानाडे एंड संस ने 5 दिसंबर, 1947 को

बैंक की संपत्ति में से रुपये 15 लाख के अधिमान्य भुगतान के लिए दावा किया। 28 फरवरी, 1949 को परिसमापक ने एक आदेश प्रस्तुत किया कि वी. आर. रानाडे। और संस को आदेश की तारीख के एक महीने के भीतर तरजीही लेनदारों के रूप में रुपये 80,000 का भुगतान किया जाए। यह राशि वास्तव में न्यायालय के निर्देश के तहत कुछ समय बाद आधिकारिक परिसमापक द्वारा वी. आर. रानाडे एंड संस को भुगतान की गई थी।

1947 की शुरुआत में बैंक ऑफ भोपाल ने अपने दलाल शांतिलाल एल थार को अपनी ओर से भोपाल सरकार के रुपये 3,00,000 के अंकित मूल्य के ऋण को खरीदने का निर्देश दिया था, और थार ने करदाता बैंक से भोपाल सरकार के ऋण खरीदने के लिए अनुबंध किया था। 11 फरवरी, 1947 को बैंक को रुपये 3,00,000 की राशि का भुगतान किया गया, लेकिन आवंटन का कोई पत्र जारी नहीं किया गया। बैंक ऑफ भोपाल लिमिटेड को ऋण प्रमाण पत्र कभी नहीं दिए गए और करदाता बैंक को भुगतान किए गए रुपये 3,00,000 बैंक की जेतपुर शाखा में बंतवा के हारून हाजी अब्दुल सत्तार के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए, जिससे पता चला कि उस व्यक्ति ने रुपये 3,00,000 मूल्य के बॉन्ड बेचे थे। इस राशि को सचिव द्वारा वापस ले लिया गया और इसका गबन किया गया। बैंक ऑफ भोपाल लिमिटेड ने भोपाल सरकार के बॉन्ड की डिलीवरी के आदेश के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एसेसी बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमे में एक समझौता हुआ और निर्धारिती बैंक ने पूर्ण और

अंतिम निपटान में बैंक ऑफ भोपाल लिमिटेड को रुपये 1,35,000 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। 20 सितंबर, 1951 को एक सहमति डिक्री पारित की गई थी, और इसके कुछ समय बाद परिसमापक द्वारा संतुष्ट किया गया था।

800. [1965]1 एस-सी-आर

98,892 रुपये की एक और राशि है जिसके बारे में परिसमापक द्वारा दावा किया गया था कि सचिव द्वारा गबन किया गया था। सुनवाई के दौरान परिसमापक के वकील ने दावे के इस हिस्से को छोड़ दिया है और इस अपील के उद्देश्य से इस राशि के संबंध में विवरण निर्धारित करना अनावश्यक है। इसलिए दूसरे प्रश्न के तहत दावा 10,15,000 रुपये तक सीमित होना चाहिए। आयकर अधिकारियों ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया। उनके विचार में यह बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान पीड़ित नहीं किया गया था और इसलिए इसे बैंक द्वारा नुकसान के रूप में नहीं माना जा सकता था, और किसी भी स्थिति में नुकसान खाते के वर्ष में नहीं हुआ था क्योंकि इसका पता वर्ष 1949 या बाद में लगाया गया था और इसे अकेले उस अवधि से संबंधित मूल्यांकन में ध्यान में रखा जा सकता था। निस्संदेह गबन 30 जून, 1947 को समाप्त होने वाले खाते के वर्ष में हुआ था। सचिव ने पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत उन्हें दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया और उन व्यक्तियों के नाम पर प्रविष्टियां पोस्ट करके रुपये

18,00,000 वापस ले लिए, जिनका अस्तित्व ही नहीं था, या जिनका बैंक के साथ कोई लेन-देन नहीं था। लेकिन जब तक बैंक के लेन-देन की जांच नहीं की जाती, तब तक गबन बैंक के निदेशकों या परिसमापक के संज्ञान में नहीं आ सका। बैंक के फंड के साथ सचिव के लेन-देन से उत्पन्न देयता को पूरा करने के लिए बैंक को अपने घटकों को रुपये 10,15,000 का भुगतान करना पड़ा। इसलिए, सचिव द्वारा की गई निकासी के परिणामस्वरूप बैंक को नुकसान हुआ है, और अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या नुकसान 30 जून, 1947 को समाप्त होने वाले खाते के वर्ष में हुआ था।

परिसमापक के वकील द्वारा यह आग्रह किया गया था कि बैंकिंग संस्थान को नुकसान तब होता है जब किसी एजेंट या नौकर द्वारा धन वापस ले लिया जाता है या दुरुपयोग किया गया है, और इसलिए खाते के वर्ष में सचिव द्वारा निकासी या गलत आवेदन किया जाता है, नुकसान उस वर्ष के मुनाफे के खिलाफ खाते के वर्ष में भत्ते के रूप में स्वीकार्य था। हम इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। अपने एजेंट द्वारा गबन के कारण करदाता को खोई गई राशि को काटने का दावा उप-धारा के तहत किसी भी भत्ते के विवरण के भीतर नहीं आता है। (2) स्वीकार्य होने के लिए, यदि ऐसा है, तो उप-धाराओं के अंतर्गत आना चाहिए। (1) बैंक के वकील द्वारा हमारे निर्णय में उच्च न्यायालय में इस स्थिति को स्वीकार किया गया था। किसी एजेंट द्वारा निधियों के दुरुपयोग से होने वाली हानि की समस्या

को वाणिज्यिक व्यापार के सिद्धांतों के संदर्भ में सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली कई अन्य समस्याओं की तरह देखा जाना चाहिए। एक एजेंट द्वारा धन का गबन, एक सट्टा साहसिक कार्य की तरह, जरूरी नहीं कि गबन होने पर तुरंत नुकसान हो, या साहसिक कार्य शुरू हो जाए। गबन प्रिंसिपल के लिए अज्ञात रह सकता है, और गबन की गई संपत्ति को एजेंट या नौकर द्वारा बहाल किया जा सकता है।

801. एसोसिएटेड बैकिंग कॉरपोरेशन बनाम सी.आई.टी (शाह जे.)

ऐसे मामले में, वाणिज्यिक अर्थ में, कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है। फिर से यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी मामलों में जब प्रिंसिपल गबन का ज्ञान प्राप्त करता है तो नुकसान होता है। गलती करने वाले सेवक को कानून की प्रक्रिया द्वारा या अन्यथा पूरी तरह से या आंशिक रूप से अपने गलत लाभ को बहाल करने के लिए राजी या मजबूर किया जा सकता है। इसलिए जब तक बहाली प्राप्त करने का एक उचित मौका मौजूद है, तब तक वाणिज्यिक अर्थों में नुकसान को परिणाम नहीं कहा जा सकता है।

एम. पी. वेंकटचलपति में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी व्यवसाय के लाभ और लाभ का पता व्यापार के सामान्य वाणिज्यिक सिद्धांतों द्वारा लगाया जाना चाहिए, और एक कामकाजी नियम यह है कि

जब तक दुरुपयोग से होने वाली हानि "वास्तविक और निश्चित नहीं हो जाती" तब तक हानि का कोई उपार्जन नहीं हो सकता है। वेंकटचलपति के मामले (1951) 20 आईएलआर 363:(एआईआर 1952 मैड 238) में करदाता ने एक क्लर्क को नियुक्त किया जो किसी व्यवसाय के बही-खाते लिखता था, सेल्समैन के रूप में काम करता था, प्रबंध भागीदार की अनुपस्थिति में नकदी प्राप्त करता था और वितरित करता था और बिल एकत्र करता था। खातों में हेरफेर करके क्लर्क ने अलग-अलग समय पर बड़ी राशि का गबन किया। मई 1941 में यह पता चला कि क्लर्क ने 17 अक्टूबर, 1939 और 24 अक्टूबर, 1940 के बीच की अवधि के दौरान रुपये 36,298-3-6 का गबन किया था, जून 1941 में क्लर्क के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा शुरू किया गया था और लगभग उसी समय राशि की वसूली के लिए एक सिविल मुकदमा भी शुरू किया गया था। अगस्त 1941 में दावे में समझौता किया गया और क्लर्क ने करदाता को अपनी देयता के पूर्ण निपटान में रुपये 16,250 का भुगतान किया। करदाता ने आकलन वर्ष 1942-43 (12 अप्रैल, 1942 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष) में रुपये 21,372/- की कटौती का दावा किया, जो क्लर्क द्वारा गबन की गई राशि और उससे वसूली गई राशि का अंतर था, और यह सही माना गया था कि इस राशि को उस अवधि के मुनाफे से कटौती योग्य लेखा अवधि में नुकसान के रूप में माना जा सकता है।

विचाराधीन मामले में बैंक की निधियों का गबन 1946 में हुआ था। तब वे बैंक के लिए अज्ञात थे। परिसमापक के संज्ञान में आने के बाद भी, ट्रेडिंग हानि को परिणामी नहीं माना जा सकता है। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अन्य विचारों के बावजूद, जैसे ही नियोक्ता के धन का गबन होता है, चाहे नियोक्ता को गबन के बारे में पता हो या नहीं, इसके परिणामस्वरूप व्यापारिक हानि होती है। जब तक बैंक द्वारा गबन की गई राशि की वसूली की उचित संभावना थी, तब तक वाणिज्यिक अर्थों में व्यापारिक हानि को परिणामी नहीं माना जा सकता है।

802. [1965]1 एस-सी-आर

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जवेरी खाते के वर्ष में सचिव पूरी तरह या आंशिक रूप से दायित्वों को पूरा नहीं कर सका होगा यदि उसे गबन की गई राशि वापस करने के लिए कहा गया था। गबन की गई राशि का पता मेसर्स एमएन रायजी एंड कंपनी की 1 अप्रैल, 1947 की रिपोर्ट से भी परिसमापक को नहीं चला, जिन्हें संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा बैंक के मामलों की जांच के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। गबन का पता परिसमापक को बहुत बाद में चला, जब परिसमापक ने उन विभिन्न व्यक्तियों से मांग की जिनके नाम पर बैंक की खाता पुस्तकों में राशि डेबिट की गई थी, और अधिमान्य भुगतान के लिए परिसमापक से मांग की गई थी वीआर रानाडे एंड संस और बैंक ऑफ

भोपाल लिमिटेड द्वारा राशि के पुनर्भुगतान के लिए या बैंक के माध्यम से उनके द्वारा खरीदे गए स्टॉक की डिलीवरी के विकल्प के रूप में।

ट्रिब्यूनल ने अपनी पूरक रिपोर्ट में पाया है कि सचिव द्वारा धन की निकासी और दुरुपयोग की जानकारी संदर्भ के तहत लेखांकन वर्ष के बाद परिसमापक को हुई, क्योंकि किसी को भी संदेह नहीं था कि खाते की पुस्तकों में पोस्ट की गई प्रविष्टियाँ झूठी थीं। सचिव द्वारा अपने व्यवहार को छुपाने के लिए प्रविष्टियाँ। यह निष्कर्ष सबूतों पर आधारित है और मामले की परिस्थितियों में, परिसमापक को गबन के बारे में पता चलने के बाद और यह पता चलने पर कि गबन की गई राशि की वसूली नहीं की जा सकती, बैंक को हुआ नुकसान माना जाना चाहिए। इसलिए धारा 10(1) के तहत व्यापारिक हानि की कटौती को आमंत्रित करने वाली प्रमुख शर्तों में से एक अनुपस्थित है। हम तदनुसार उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि रुपये 10,15,000/- की राशि धारा 10(1) के तहत अनुमेय कटौती नहीं थी।

इसलिए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए पहले प्रश्न का उत्तर जारी किया जाएगा, और यह दर्ज किया जाएगा कि बैंक धारा 10(2) (xi) के तहत दावा करने का हकदार है।

30 जून, 1947 को समाप्त होने वाले खाते के वर्ष में रुपये 15,00,000/- अशोध्य ऋण के रूप में दर्ज किया जाए। दूसरे प्रश्न पर,

उत्तर नकारात्मक होगा। इस अपील में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भंवर भदाला (आर.जे.0347) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।